

टायर इंडस्ट्री को Q4 में ग्रोथ सुस्त रहने का डर

कृष्ण कुमार पीके | कोच्चि |

टायर इंडस्ट्री ने आशंका जताई है कि नकदी की समस्या और लोकसभा चुनाव के चलते वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में टायर बिक्री की ग्रोथ सुस्त रह सकती है। दिवाली के बाद इंडस्ट्री को कमजोर डिमांड का सामना करना पड़ा और इस महीने भी ऐसा ही ट्रेंड बना रहा। ऐसे में इंडस्ट्री इस वित्त वर्ष की पहली छमाही में दिखी तेज ग्रोथ का सिलसिला जारी रहने की उम्मीद नहीं कर रही है।

अप्रैल से नवंबर के दौरान मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल (एमएचसीवी) टायर्स की बिक्री 3 लाख यूनिट्स की रही, जो पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 55 पसैंट ज्यादा थी। टायर कंपनियों की आमदनी का एक बड़ा एमएचसीवी के जरिए आता है। ऑटोमोटिव टायर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (एटीएमए) के डायरेक्टर जनरल राजीव बुद्धराजा ने कहा, 'नवंबर में ग्रोथ नरम पड़ गई और दिसंबर में इसके सिंगल डिजिट में आ जाने की आशंका है।' अप्रैल से नवंबर के

■ NBFC के लिक्विडिटी क्राइसिस ने भारी गाड़ियों के टायरों की बिक्री पर असर डाला है, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ने का असर टू-व्हीलर्स की बिक्री पर पड़ा है

दौरान ट्रैक्टर टायरों के सेगमेंट में भी ग्रोथ देखने को मिली। हालांकि, इस साल कुल 6.45 लाख ट्रैक्टर टायर्स की बिक्री हुई और पिछले साल के मुकाबले इसमें 18 पसैंट की ही बढ़ोतरी हुई। राजीव ने कहा कि पैसेंजर कार और टू-व्हीलर टायरों की बिक्री में सिंगल डिजिट ग्रोथ रही। IL&FS के डिफॉल्ट करने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर सामान्य तौर सुस्ती देखने को मिली है, जिसने डिमांड पर बुरा असर डाला। राजीव ने कहा, 'एमएचसीवी टायर्स की बिक्री काफी हद तक एनबीएफसी सेगमेंट पर निर्भर करती है। नकदी की समस्या के चलते भारी गाड़ियों के मालिकों के पास काफी कम वित्तीय विकल्प बचे हैं।' कार मार्केट में नए लॉन्च की संख्या काफी कम रही, जिसने टायर मार्केट को प्रभावित किया। वहीं, इंश्योरेंस कॉस्ट में इजाफे ने टू-व्हीलर्स की बिक्री को प्रभावित किया। मौजूदा वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही के दौरान चुनाव भी होने वाले हैं। राजीव का मानना है कि यह इंडस्ट्री के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होगा। उन्होंने कहा, 'सरकार चुनावी सीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के बजाय ग्रामीण और पब्लिक सेक्टर की योजनाओं पर ज्यादा ध्यान देगी। एमिशन नॉर्म्स को बदलकर बीएस-4 से बीएस-6 करना इंडस्ट्री के लिए दूसरा सिरदर्द साबित होगा।' अगर रॉ मैटीरियल की बात की जाए तो इंडस्ट्री काफी हद तक नेचुरल रबड़ के आयात पर ही निर्भर है। इंडस्ट्री के पास बिक्री न होने के चलते काफी सारी इनवेंटरी बची हुई है। किसान भी कम कीमत और मुनाफे के चलते टैपिंग से परहेज कर रहे हैं। कोचीन रबड़ मर्चेण्ट्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी विकास अग्रवाल का कहना है, 'टायर कंपनियों की ओर से डिमांड काफी कमजोर है। वहीं, लोकल रबड़ की अवलेबिलिटी काफी ज्यादा है। रबड़ की कम कीमतों के चलते आने वाले समय में भी सप्लाइ में कमी की समस्या जारी रह सकती है।'